आदिवासी आज भी "स्नल" जिस हिन्दी में घोघा कहते हैं, उस खा रहे हैं। एक दो परिवार नहीं, हजारों की तादाद में जुलाई महीने से खा रहे हैं। हमारे आदिवासी लोग जो जंगल की जड़ जो तीती और जहरीली होती है, उस को गरम पानी में उबाल कर महीनों से खा रहे हैं, क्योंकि न तो उन्हें अन्न मिल रहा है और न ही उन के पास कोई काम-धन्धा है। हमारा छोटा नागपुर का इलाका, जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां की जनता इस जंगल-जड़ और अन्यत्र खाद्य-पदार्थों पर पिछले छः महीने से जीवन-यापन कर रही है, जिस के परिणामस्वरूप उन के ऊपर तरह-तरहके रोगों का आक्रमण हो रहा है, काला-ज्वर का आक्रमण हो रहा है।

पिछले 10 अक्तूबर का पूर्णिया में डी० डी० सी० की मीटींग में मैंने इस सवाल को उठाया था कि इस तरह के बेकार लोगों को "फूड फार वर्क" स्कीम के अन्तर्गत दिया जाये। लेकिन वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न मुझे जवाब दिया—चूंकि फूड कार्पोरेशन आफ़ इण्डिया की तरफ से हमें अनाज नहीं दिया जा रहा है, इसलिये हमारे सामने लाचारी है कि हम ऐसे लोगों को अनाज देकर काम करायें और उन की जीवन रक्षण कर सकें। मैं दो बार वहां पर जा चुका हूं और नवम्बर महीने में भी मैंने उन की वही स्थिति देखी? ये लाखों, करोड़ों लोग जो भुखमरी के कगार पर खड़े हैं, उन के लिए कोई स्कीम नहीं है और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे उस को इस कष्टमय जीवन से बचाया जा सके। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि वह जल्द से जल्द ऐसे कोई कदम उठाए जिनसे आयन्दा ऐसी कोई बात न हो कि वे दाने-दाने के लिए मोहताज हो जाए।

(ii) REPORTED ARREST OF KHAN ABDUL GHAFFAR KHAN IN PAKISTAN

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Sir, this House, on an earlier occasion, also expressed grave anxiety about the illness of Khan Abdul Gaffar Khan. I had the occasion to express the anxiety about his illness. As this relates to a certain diplomatic norm, kindly allow me to read the small brief which I have written instead of making a speech on the matter.

MR SPEAKER: Yes.

SHRI SAMAR GUHA: Sir, we feel greatly disturbed by the news of the arrest of Khan Abdul Ghaffar Khan, who is now 95 years old. Although he is now a national of Pakistan, yet we cannot forget his immense contribution to the independence struggle of our country. He was endearingly known to all of us in the country, which is now known as the Indian Sub-Continent, as Badshah Khan and Frontier Gandhi. He is respected as equally in our part of the country as in Pakistan. Remembering the history of our freedom struggle and our great respect for the Frontier Gandhi, we appeal to the Government of Pakistan on humanitarian grounds to release him and allow him to live in a place wherever he wants so that he may pass the last days of his life peacefully. A great Khoda-e-khidmatgar a servant of God, like him should be given that freedom. We hope our appeal will receive necessary response from the Government of Pakistan, and their administration will not consider this expression of our anxiety for Badshah Khan as any interference in their internal affairs in a narrow technical diplomatic sence.

(iii) DEMONSTRATION BY WORKERS OF RAILWAYS, DEFENCE UNDERTAKINGS ETC. FOR 8.33 PER CENT BONUS.

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): Sir, Yesterday, the workers of the railways, defence undertakings, P&T and CPWD belonging to INTUC

[Shri Saugata Roy]

demonstrated at the Boat Club insisting on their demands for a 8.33 per cent bonus.

A deputation of the workers also met you and submitted to you a memorandum listing their demands and asking for permission to raise the same matter in the House.

As the Railway Minister here is aware, there is a great discontent among the railway employees on their being deprived of their bonus which was restored to the workers in the industrial establishments and the public sectors by the Government Ordinance on 8th August, 1977. This is leading to disruption in the working of the railways.

Now, the question is not only the workers in these departmental undertakings which are governed by the Factories Act and the Industries (Development and Regulation) Act where the workers can form a union under the Trade Union Act but they will also be treated at par with their counterparts in other industrial undertakings. So, the Government's decision in this regard is ominous silence in regard to the Central Government employees, defence, railways, P&T and other departmental undertakings. I want to mention to you about the demands of the Defence employees, that is, the employees in the Ordnance Factories which have been represented by the Indian National Defence Workers' Federations belonging to the INTUC. I happen to be the Working President of the Federation. Not only that. In my own constituency, one of the biggest Ordnance Factories is at Ichhapur there are 18,000 defence employees working. Naturally, their hopes first of all have been belied in the Government's denial of the right or bonus to them. Secondly, a large number of problems relating to Defence employees are pending before the Government for a long time.

And they include their demand for classification; they include the demand for better D.A. I quote from their memorandum:

> "The promise of refund of Compulsory Deposits has yet to be redeemed. The workers are getting agitated and restless on this account."

They relate to the demand of canteen employees and the school teachers in the different Defence and Ordnance factories. They also relate to the class IV employees and the Mazdoors.

I take this opportunity to apprise you and through you the House of the great discontent that there is today among the workers in these departmental undertakings who very much expect that some of their leaders who were associated with them in the trade union movement and have now become Ministers that these demands will be fulfilled by them. But their hopes are belied. Sir, when the Congress government decided to cut the bonus rate we, as trade-unionists, felt unhappy and many of us expressed our unhappiness on this question and now I again want to emphasise that this demand should be considered.

If Government do not have money to give bonus to the employees, they should have at least conceded their demand for bonus. The railway employees have said even if bonus of rupee one was given they would have understood that the Government has conceded their demand for bonus. The attitude of the Government has saddened the Railways, Defence and P & T departmental undertakings employees. So, on the occasion of the demonstration of the workers before the Parliament House I take this opportunity of presentation of their memorandum to the Speaker for bo-

nus and rightful share in the profits of these undertakings.

(iv) ACUTE SHORTAGE OF EDIBLE OILS LIKE MUSTARD AND RAPE-SEED OILS RISE IN KEROSENE OIL PRICE AND NON-AVAILABILITY OF CONTROLLED CLOTH IN FAIR PRICE SHOPS IN RURAL AREAS.

श्री युवराज (कटिहार) : मान्यवर, इस देश की सब स पिछड़ी जनता गांवों में बसती है ? उस पिछड़ी जनता की आबादी इस देश में 82 फीसदी है। जिन उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण आजकल सरकार कर रही है, उनका वितरण देश की सब से पिछड़ी जनता तक ठीक से नहीं हो पाता । जो सरसों का तेल या रेपसीड आयल और सस्ता कपड़ा कंट्रोल की दुकानों द्वारा मुहैया किया जाता है उसका प्रबंध इन गरीब लोगों के लिए अच्छी प्रकार से नहीं हो पा रहा है । इन चीजों का थोड़ा बहुत प्रबंध शहरं. क्षेत्रों में तो पाया जाता है लेकिन देश के साढ़े पांच लाख देहातों में जो देश की 82 प्रतिशत जनता बसती है उसके लिए इसकी व्यवस्था का नितान्त अभाव है । देहातों में सरसों के तेल की नितान्त कमी है, रेपसीड आयल की नितान्त कमी है । देहातियों को पांच रुपये तक अधिक मूल्य देना पड़ता है । जो लोग एक-दो रुपये रोज की मजदूरी करते हैं वे कैसे इन चीजों को खरीद सकते हैं?

सरकार ने कपड़े सस्ती दर पर आपूर्ति के लिए दुकानें खोली हैं। वह कपड़ा भी उनको नहीं मिल पाता है । जो यह सस्ती दर का कपड़ा उपलब्ध है वह ऐसी क्वालीटी का है कि जो कपड़ा पहले 6 महीने चल जाता था, यह कपड़ा तीन-चार महीने में ही फट जाता है।

राशन की दुकानों में तेल नहीं मिलता, रेपसीड तेल नहीं मिलता है । सस्ते कपड़े की दुकानों में सस्ती दर के कपड़े की कमी है। इन चीजों का संबंध इस देश की गरीब जनता से इस देश की ये खेतिहार जनता से है । जिन जीवनोपयोगी चीजों का इस देश की ग्रामीण जनता से संबंध है वे आज उपलब्ध नहीं हैं। कहीं भी देहात में आज कड़वा तेल नहीं मिलता है । अगर आप इसको अधिक मूल्य दे कर खरीदना चाह तो आपको मिल जाएगा। जिस किसी सामान का आप अधिक दाम देना चाहे वह सामान आपको मिल जाएगा। देहातों में जो गरीब लोग हैं, खेतीहर मजदूर हैं उनकी क्रय शक्ति नष्ट हो गई है और वे अधिक मूल्य पर इन जीवन नोपयोगी वस्तुओं को खरीद नहीं सकते हैं । तेल तो गायब हो ही गया है कैरोसीन तेल भी देहात में रहने वाले लोगों को, खेतीहर मजदूरों को नहीं मिलता है। अगर यों कहा जाए कि वे अंधेरे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो कोई आतिशयोक्ति नहीं होगी।

आज भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया है । सप्लाई विभाग के लोग इसमें लिप्त हैं । सप्लाई इंस्पैक्टर, प्रत्येक प्रखंड के बी० डी० ओ० और प्रत्येक जिले में जो सप्लाई अफसर हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । इसलिए देश में आज असन्तोष फैलता जा रहा है । वितरण की जो प्रणाली है वह अत्यन्त ही असन्तोषप्रद है, अपर्याप्त है । सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है । आप देखें कि भारत सरकार के आपूर्ति मंत्री ने तेल का आवंटन किया, तेल का एलाटमेंट किया तो अभी कुछ दिन पहले हमारे मंत्री जी श्री मोहन धारिया ने कहा था कि अगर किसी राज्य में किसी क्षेत्र में तेल की कमी हो, रेपसीड आयल की कमी हो तो उन्हें पत्र लिखा जाये और वह चार दिनों के अन्दर-अन्दर वहां तेल की आपूर्ति कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने उसी दिन एक पत्र उनको लिखा लेकिन चार दिन के बजाय आज एक सप्ताह बीत गया, इसकी आपूर्ति की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है । स्थिति दिन प्रति दिन बद से बदतर होती जा रही है। देहातों की